

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942-अगस्त 21, 2020 <i>Sravana 30, Friday, Saka 1942-August 21, 2020</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(24)विशा/विस/2020 :-राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक सं.24

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (114) के विद्यमान उप-खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में,-

- (i) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "का प्रदाय" से पूर्व अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के किसी अंतरराज्यिक जावक" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी; और
- (iii) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "माल" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के किसी प्रदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या सेवाओं" अंतःस्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "नामे नोट संबंधित है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छा से कराये गये रजिस्ट्रीकरण को छोड़ने का आशय रखता है;"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायें, ऐसी कालावधि,-

(क) अपर आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिवस से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अतिरिक्त तीस दिवस से अनधिक की और कालावधि के लिए,

बढ़ायी जा सकेगी।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) ऐसी सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में कर बीजक ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, जारी किया जायेगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में-

- (i) प्रदाय के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जायेगा; या
- (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।"

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, जारी किया जायेगा।"; और

(ख) विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1क) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) के अंतर्गत आने वाले किसी संव्यवहार का फायदा प्रतिधारित करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किये गये या हस्तान्तरित इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम की शास्ति का दायी होगा।"

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 132 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो कोई भी निम्नलिखित किन्हीं अपराधों में से कोई अपराध कारित करता है या कारित करवाता है और उससे उदभूत फायदों को प्रतिधारित करता है" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है"; और

(iii) उप-खण्ड (ड) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग" हटायी जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 140 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रकम, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा करने का हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रकम की जमा, यदि कोई हो, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रणीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति से नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस लेने को समाप्ति कालावधि के लिए हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", जो नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी में अग्रणीत नहीं की गयी है, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये,

अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ग) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिवस को मूल्य परिवर्धित कर के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिवस को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा को, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(घ) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्य परिवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मूल्य परिवर्धित कर की जमा, यदि कोई हो, को ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया गया है कि" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ङ) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिवस को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित माल के इनपुट को स्टॉक में धारित स्टॉक और इनपुट के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संदाय कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिवस को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा को, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 172 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो," और खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो," हटायी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से हटायी हुई समझी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

- (i) विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (114) के उप-खण्ड (ग) और (घ) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 44) के अनुरूप किया जा सके।
- (ii) विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त धारा की उप-धारा (1) और उप-धारा (2क) के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प चुनने हेतु पात्रता की शर्तों को सुमेलित किया जा सके।
- (iii) विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किये जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किये जाने की तारीख को असंबद्ध किया जा सके।
- (iv) विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छा से कराये गये रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का उपबंध किया जा सके।
- (v) विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उप-धारा (1) के परन्तुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे अधिकारिता रखने वाले कर प्राधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन फाइल करने के लिए उपबंधित अवधि को बढ़ाये जाने हेतु सशक्त किया जा सके।
- (vi) विधेयक का खण्ड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उप-धारा (2) के परन्तुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे सरकार को, उन सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जायेगा तथा उनके जारी किये जाने के समय और रीति से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।
- (vii) विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 को संशोधित किये जाने के लिए ईप्सित है, जिससे सरकार को ऐसा प्ररूप और रीति,

जिसमें स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

- (viii) विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 में एक नयी उप-धारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कतिपय संव्यवहारों के हिताधिकारी को, जिसके अनुरोध पर ऐसे संव्यवहार किये जाते हैं, शास्ति के लिए दायी बनाया जा सके।
- (ix) विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे किसी बीजक या बिल के बिना कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के अपराध को धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन संज्ञेय और अजमानतीय बनाया जा सके और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कतिपय संव्यवहारों के फायदे को प्रतिधारित करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसे संव्यवहार किये जाते हैं, दण्ड के लिए दायी बनाया जा सके।
- (x) विधेयक का खण्ड 11 इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं से संबंधित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे विद्यमान विधि के अधीन कतिपय उपभोग न किये गये प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए समय-सीमा और रीति विहित की जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।
- (xi) विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तदधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय-सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।
- (xii) विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 के पैरा 4 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे अभिव्यक्ति "चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो," और अभिव्यक्ति "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो," को हटाया जा सके और उक्त पैरा की प्रविष्टि (क) और (ख) के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 1 जुलाई, 2020 को राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 7) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 1 जुलाई, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 की उप-धारा (2) के परन्तुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि सरकार को कर बीजक जारी करने के समय और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 8, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उप-धारा (3) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति का, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा, उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 11, विद्यमान विधि के अधीन कतिपय अनुपभुक्त प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए समय-सीमा और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने के लिए ईप्सित है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT) BILL,
2020**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-clauses (c) and (d) of clause (114) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(d) Ladakh;”.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 10 of the principal Act,-

(i) in clause (b), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “which are”, the expression “or services” shall be inserted;

(ii) in clause (c), after the existing expression “of goods” and before the existing punctuation mark “;”, the expression “or services” shall be inserted; and

(iii) in clause (d), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “through an”, the expression “or services” shall be inserted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the existing expression “invoice relating to such” shall be deleted.

5. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:”.

6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(ii) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,-

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.

7. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing proviso to sub-section (2) of section 31 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,-

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which-

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.”.

8. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 51 of the principal Act,-

(a) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.”; and

(b) the existing sub-section (4) shall be deleted.

9. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.

10. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “Whoever commits any of the following offences”, the expression “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences” shall be substituted;

(ii) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely:-

“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;

(iii) in sub-clause (e), the existing expression “, fraudulently avails input tax credit” shall be deleted.

11. Amendment of section 140, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,-

(a) in sub-section (1), after the existing expression “existing law” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the existing expression “appointed day” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (3), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (5), for the existing expression “existing law”, the expression “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted; and

(e) in sub-section (6), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.

12. Amendment of section 172, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (1) of section 172 of the principal Act, for the existing expression “three years”, the expression “five years” shall be substituted.

13. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In paragraph 4 of Schedule II of the principal Act, the existing expression “whether or not for a consideration,” wherever occurring, shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 7 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

The Rajasthan Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2020, *inter alia*, provides for the following, namely:-

- (i) Clause 2 of the Bill seeks to amend sub-clauses (c) and (d) of clause (114) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to align the definition of “Union territory” in line with the Jammu and Kashmir Re-organization Act, 2019 (Central Act No. 34 of 2019) and the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories), Act, 2019 (Central Act No. 44 of 2019).
- (ii) Clause 3 of the Bill seeks to amend clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to harmonise the conditions for eligibility for opting to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2A) of the said section.
- (iii) Clause 4 of the Bill seeks to amend sub-section (4) of section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of the underlying invoice for purposes of availing input tax credit.
- (iv) Clause 5 of the Bill seeks to amend clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for cancellation of registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25.
- (v) Clause 6 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (1) of section 30 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the jurisdictional tax authorities to extend the period provided to file an application for revocation of cancellation of registration.
- (vi) Clause 7 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (2) of section 31 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government to notify the categories of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued and to make rules regarding the time and manner of its issuance.
- (vii) Clause 8 of the Bill seeks to amend section 51 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government to make rules to provide for the form and manner in which a certificate of tax deduction at source shall be issued.
- (viii) Clause 9 of the Bill seeks to insert a new sub-section (1A) in section 122 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to make the beneficiary of certain transactions at whose instance such transactions are conducted liable for penalty.
- (ix) Clause 10 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 132 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to make the offence of fraudulent availment of input tax credit without invoice or bill cognizable and non-bailable under sub-section (1) of section 69 and to make any person who retains the benefit of certain transactions and at whose instance such transactions are conducted liable for punishment.
- (x) Clause 11 of the Bill seeks to amend section 140 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 relating to transitional arrangements for input tax

credit, so as to prescribe the time limit and the manner for availing input tax credit against certain unavailed credit under the existing law. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

- (xi) Clause 12 of the Bill seeks to amend section 172 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to extend the time limit provided for removal of difficulties thereunder from three years to five years, with effect from the date of commencement of the said Act.
- (xii) Clause 13 of the Bill seeks to amend paragraph 4 of Schedule II to the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to delete the expression “whether or not for a consideration,” and to give clarity to the meaning of the entries (a) and (b) of said paragraph. This amendment shall take effect retrospectively from the 1st day of July, 2017.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 7 of 2020), on 1st July, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 1st July, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to amend proviso to sub-section (2) of section 31 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government to make rules to provide for the time and manner of issuing tax invoice.

Clause 8 of the Bill seeks to amend sub-section (3) of section 51 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Government to make rules to provide for the form and manner in which a certificate of tax deduction at source shall be issued.

Clause 11 of the Bill seeks to amend section 140 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 with retrospective effect to empower the State Government to make rules to provide for the time limit and the manner for availing input tax credit against certain unavailed credit under the existing law.

The matters in respect of which the rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.